

भारत सरकार  
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1303  
मंगलवार, 30 जुलाई, 2024/8 श्रावण, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना

+1303. श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) क्या इससे देश में सहकारी आंदोलन में वृद्धि होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) भारत में और वैश्विक स्तर पर सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडलों के विकास को किस प्रकार प्रभावित करने की आशा है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क), (ख) और (ग): सहकारी क्षेत्र में संबद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा प्रदान करने, सहकारी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए सहकारिता मंत्रालय एक राष्ट्र-स्तरीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर कार्य कर रहा है।

उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय की रूपरेखा विकसित करने हेतु केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों, इत्यादि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ गहन परामर्श किए गए। यह विश्वविद्यालय अपने व्यय की पूर्ति के लिए प्रचालनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनने को भी लक्षित होगा।

प्रस्तावित विश्वविद्यालय द्वारा सहकारी क्षेत्र के साथ समन्वित तरीके से कार्य करने की संभावना है और यह सहकारी क्षेत्र में मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए स्थायी, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण श्रमबल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का व्यापक, एकीकृत और मानीकृत संरचना होगी। पेशेवर श्रमबल की आपूर्ति और मौजूदा कर्मियों के क्षमता निर्माण से सहकारी क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक योगदान किया जा सकेगा।

\*\*\*\*\*